भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4065

दिनांक 30 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

उत्तराखंड में पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों का संरक्षण

4065. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड राज्य में सूखते जल स्रोतों और पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कोई विशेष कार्य योजना लागू की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): जल के राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं से संबंधित पहलुओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार विभिन्न चालू स्कीमों के अंतर्गत जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उत्तराखंड राज्य में जल संसाधन विकास और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के साथ क्रमश: 57.07 हजार हेक्टेयर और 33.78 हजार हेक्टेयर की अधिकतम सिंचाई क्षमता वाली उत्तराखंड की दो प्रमुख परियोजनाएं नामत: जमरानी बांध परियोजना और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई हैं। दो परियोजनाओं का संयुक्त सक्रिय भंडारण 473.12 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से 19.52 हजार हेक्टेयर की अधिकतम सिंचाई क्षमता के साथ 422 सतही लघु सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं।

- इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) भूजल प्रबंधन एवं विनियमन स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (नैक्यूम) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। उत्तराखंड में 11,430 वर्ग किलोमीटर सहित देश में लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जलभृत मानचित्रण का कार्य पूरा हो चुका है। कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त जल संरक्षण और पुनर्भरण उपायों सहित प्रबंधन योजनाओं के साथ जलभृत मानचित्रों को राज्यों के साथ साझा किया गया है।

- सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान (2020) तैयार किया है जो उत्तराखंड राज्य सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक वृहद स्तरीय योजना है। भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के लिए 15,523 संरचनाओं को चिन्हित किया गया है। मास्टर प्लान को कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है।

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वाटरशेड विकास और पारंपरिक जल निकायों के पुनरूद्धार को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन और जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम शुरू किया है। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में 1,300 पारंपरिक जल निकायों का पुनरूद्धार किया गया है, 646 पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है और 18,356 वाटरशेड विकास कार्य पूरे किए गए हैं। इसके अलावा, जल संचय जनभागीदारी 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड में 3,626 कार्य पूरे किए गए हैं।

*****